विवरण

खाद्यान्नों की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता दिखाने वाला विवरण

राज्य	उत्पादकता किग्रा०/हैक्टेयर 1995-96
आंध्र प्रदेश	1719
अरुणाचल प्रदेश	1201
असम	1306
बिहार	1465
गोआ	2063
गुजरात	1094
हरियाणा	2537
हिमाचल प्रदेश	1615
जम्मू और कश्मीर	1541
कर्नाटक	1292
केरल	1902
मध्य प्रदेश	1020
महाराष्ट्र	879
मणिपुर	2511
मेघालय	1163
मिजोरम	1589
नागालैंड	1235
उड़ीसा	1088
पंजाब	3472
राजस्थान	805
सिक्किम	1351
तमिलनाडु	2148
त्रिपुरा	1951
उत्तर प्रदेश	1886
पश्चिम बंगाल	1985
अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह	2329
दादर और नगर हवेली	1471
दमन और दीव	
दिल्ली	3386
पांडिचेरी	2176
अखिल भारत	1499

National Centre for Training of Women in Agriculture in Maharashtra

2109. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government propose to establish a National Centre for imparting training in Agriculture to women at Nagpur in Maharashtra;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(c) in what way Government propose to impart training to women in Agriculture in Maharashtra, particularly in Vidarbha region of the state?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) No., Sir.

(b) To impart training to women farmers in the field of agriculture and allied sectors, the Central Government has launched a Central Sector Scheme of 'Training of Women in Agriculture' on pilot basis in one district of each of the seven selected states of the country *viz.* Punjab, Haryana, U.P., H.P., Maharashtra, Kerala and Rajasthan during the 8th Five Year Plan.

In Maharashtra, Thane district has been selected for this pilot effort.

(c) It is proposed to extend this scheme in the 9th Five Year Plan in one/two more districts of already selected states. The new districts will, however, be chosen in consultation with the State Government.

खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हेतु उपाय

2110. **श्री इकबाल सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार धान, गेहूं, ज्वार, मक्का, सरसों, चना, उर्द आदि का उत्पादन बढ़ाने और इन वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु क्या उपाय कर रही है; और

(ख) खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने हेतु देश-भर में, विशेष रूप से पंजाब में किसानों को नवीनतम जानकारी, प्रशिक्षण और विशेष सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में सरकार की क्या नीति है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) धान, गेहूं, ज्वार, मक्का, सरसों बीज, चना एवं उड़द इत्यादि के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के पूरक के रूप में निम्नलिखित केंद्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं:—

1. गेहूं आधारित फसली प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई०सी०डी०पी०—गेहूं)

2. चावल आधारित फसली प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई०सी०डी०पी०—चावल)

3. मोटे अनाज आधारित फसली प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई०सी०डी०पी०—मोटे अनाज)

4. त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (ए०एम०डी०पी०)

5. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ०पी०पी०)

6. राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम (एन०पी०डी०पी०)

7. उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रचार सहित चावल, गेहूं, मोटे अनाज का बीज मिनिकिट कार्यक्रम।

वांछनीय विशेषताओं के साथ किस्मों के विकास के लिए आनुवंशिक सुधार इन फसलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) पंजाब सहित अन्य राज्यों मे भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में किसानों को फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी की जानकारी प्रशिक्षण, प्रदर्शन, संचार माध्यमों इत्यादि द्वारा दी जा रही है।

राज्यों में उर्वरकों का आवंटन

2111. **श्री अजीत जोगी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों को कितनी-कितनी मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता थी और सरकार द्वारा वास्तव में इनकी कितनी-कितनी मात्रा आवंटित की गई;

(ख) चालू खरीफ और रबी मौसमों के दौरान कितने उर्वरकों का आवंटन किया गया है;

(ग) क्या वर्ष 1996-97 के दौरान इन आवंटनों में वृद्धि किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार प्रतिवर्ष खेती की अवधि के दौरान "यूरिया" के होने वाले अभाव को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए कोई प्रभावी उपाय करेगी?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के लिए मध्य प्रदेश सहित यूरिया की और वर्ष 1993-94 तथा खरीफ 1994 के लिए अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड तथा कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट, जो इस अवधि के दौरान सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन थे, की राज्य-वार आवश्यकता, आवंटन तथा खपत तथा खरीफ 1996 और रबी 1996-97 के दौरान यूरिया का राज्य-वार आवंटन प्रदर्शित करने वाला विवरण का ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है **[देखिए परिशिष्ट 180 अनुपत्र सं० 47]**

(ग) तथा (घ) यदि आवंटन में कोई वृद्धि की जानी हो तो वह राज्य सरकारों के अनुरोध पर की जाती है और वर्तमान में किसी भी राज्य से यूरिया के आवंटन में वृद्धि के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) विभिन्न राज्यों को यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, उत्पादन अधिप्राप्ति, संचलन तथा वितरण के लिए उत्तरदायी संगठनों के बीच घनिष्ठ सम्पर्क रखा जाता है। इसके अतिरिक्त बिक्री तथा उपलब्धता की समीक्षा के लिए आवधिक बैठकें की जाती हैं ताकि सुधारक उपाय किए जा सकें।

Streamlining The Procedure for Registration of Imported Pesticides

2112. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that registration requirement for imported pesticides in Asia-Pacific region is lengthy and time consuming;

(b) whether Government have received any demand from the Pesticides Forumulators Association of India and if so, the details thereof; and

(c) whether Government propose to take steps to get the prodcedure streamlined and if so, the details thereof?